बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 146

अतीत की गलतियों में सुधार

जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया शुरू करके और राज्य को केंद्र शासित क्षेत्र में विभाजित करने संबंधी विधेयक पेश करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र के एक अहम वादे को पूरा करने की ओर साहसिक और निर्णायक कदम उठाया है। बहरहाल, सोमवार की घटनाओं से कई बातें निकलती हैं। इनमें सबसे अहम यह है कि जिस तरह सरकार ने जम्मू कश्मीर का दर्जा बदलने की कोशिश की है, उससे उस तरह के एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो उसकी राजनीतिक परियोजना में परिकल्पित है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 72 वर्ष पुराने विशेष स्वायत्त दर्जे को समाप्त करके कुछ ऐतिहासिक गलतियों में सुधार किया गया है। जब भारतीय गणराज्य में अपनी रियासत का विलय करने वाले अन्य राजाओं की तरह कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे तो यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर क्यों जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अलहदा कानून के तहत रहने दिया गया। इन कानूनों के अधीन देश के अन्य राज्यों के लोगों के जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने तक पर रोक थी।

व्यापक तौर पर देखें तो अनुच्छेद 370 के खात्मे के पीछे एक दलील है। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 की धारा 3 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को किसी भी समय समाप्त कर सके। अनुच्छेद 370 (3) में कहा गया है, 'इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के जरिये यह घोषित कर सकते हैं कि इस अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है या कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ यह लागू रह सकता है। वह ऐसा किसी भी तय तिथि से कर सकते हैं।' इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया और भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के एक अहम वादे को क्रियान्वित किया गया। इन दलीलों के बावजूद मौजूद कानूनी उलझाव और संवैधानिक सवाल यह गारंटी देते हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। वही तय करेगा कि राज्य संविधान सभा की सहमति का अर्थ क्या विधायी सभा से है या नहीं। कुछ मायनों में यह एक संवैधानिक आघात है क्योंकि अब न तो राज्य विधानसभा है, न राज्य सरकार। ऐसे में राज्यपाल और संसद के लिए गुंजाइश बनी कि वे अपने बूते कदम उठा सकें। अगर राज्य विधानसभा और सरकार होतीं तो यह संभव न होता। विधानसभा चुनावों में देरी इसी तैयारी का सोचा समझा हिस्सा थी।

सरकार ने इस बड़े बदलाव के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया वह बड़ी चिंता का विषय है। राज्य के दर्जे में व्यापक बदलाव का निर्णय स्थानीय नेताओं या राज्य के लोगों के साथ मशविरे से भी किया जा सकता था। अनुच्छेद 370 ऐसी ही अपेक्षा करता है। इसके बजाय सरकार ने राज्य में सैनिकों की तादाद बढ़ाई, कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट सेवा बंद की और राज्य के प्रमुख नेताओं को नजरबंद किया। दूसरा सवाल यह है कि इससे राजनीतिक रूप से क्या हासिल हुआ? गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण राज्य का विकास रुका हुआ था और रोजगारपरक निवेश नहीं आ पा रहा था। यह दलील गलत है। विकास की कमी का कारण निरंतर चली आ रही अशांति है। विशेष दर्जे से इतर इसका कारण यह है कि यह पाकिस्तान से लगा विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान ने अलगाववादियों और आतंकवादियों को भड़काने को ही लक्ष्य बना रखा है। जरूरत थी विश्वास बहाल करने वाले उपायों की लेकिन हमारी सरकारें इसमें लगातार नाकाम रहीं।

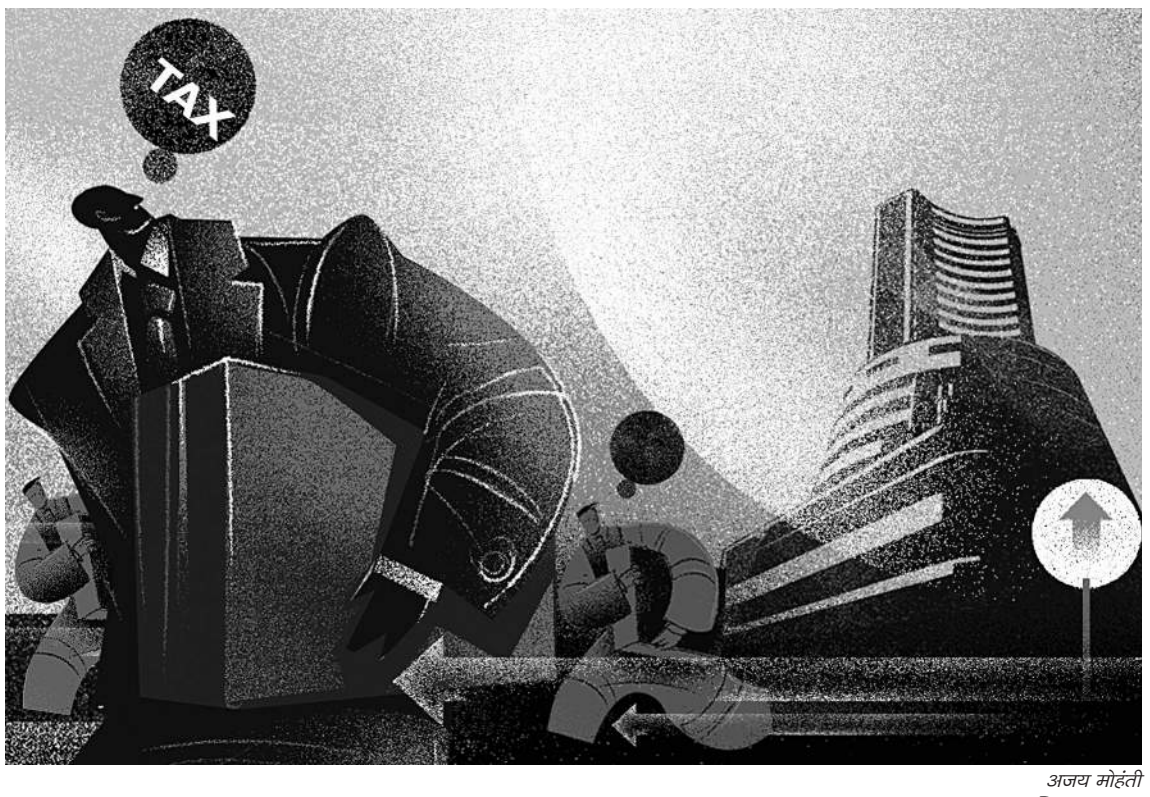

अजय मोहंती

विदेशी निवेशक क्यों कर रहे बिकवाली?

वैश्विक और घरेलू निवेशक बने रहें, इसके लिए हमें भारत को कारोबारी दृष्टि से सहज-सुगम देश बनाने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **आकाश प्रकाश**

हाल के दिनों में हमने देखा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय प्रतिभूतियों में काफी बिकवाली की। जुलाई में यह बिकवाली 250 करोड़ डॉलर के करीब रही और अब इसमें इजाफा हो रहा है। दुनिया भर के बाजार जहां नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, वहीं हम सकारात्मक बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। शीर्ष 50 बाजारों की सूची में प्रदर्शन के आधार पर हमारी रैंकिंग 43वीं है। आश्चर्य की बात यह है कि अनुकूल माहौल के बावजूद हमारा प्रदर्शन खराब रहा।

निवेशक जो सरकार चाहते थे वह और प्रभावशाली बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई है। तेल कीमतें स्थिर हैं और एक तय दायरे में नजर आ रही हैं। रुपया स्थिर है बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद उसमें कुछ मजबूती आई है। वैश्विक स्तर पर नकदी सहज उपलब्ध है और दरों में गिरावट आ रही है। केंद्रीय बैंक एक बार फिर मौद्रिक शिथिलता अपना सकते हैं। इनमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक दोनों शामिल हैं।

दिलचस्प है कि विश्व स्तर पर निवेश श्रेणी के प्रपत्रों में से करीब 25 फीसदी का प्रतिफल नकारात्मक है। प्रतिफल इतना कमजोर होने और उसमें लगातार गिरावट आने के कारण वृद्धि को तरजीह दी जानी चाहिए। भारत को हमेशा एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया है जो लंबी अवधि तक स्थायित्व भरी वृद्धि देने में सक्षम है। इसमें दो राय नहीं कि आने वाले दशक में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश होगा और वह चीन से तेज वृद्धि हासिल करेगा। इस परिदृश्य के बावजूद भारतीय बाजार संघर्ष क्यों कर रहे हैं?

इसके कई कारण हैं लेकिन मेरी नजर में सबसे अहम कारण इस प्रकार हैं:

कारोबारी आय में वृद्धि न होने से हताशा का माहौल है। बीते आठ साल में यह देश के शेयर बाजारों के लिए सबसे बड़ी निराशा की वजह रहा है। कुछ ही लोगों को अंदाजा होगा कि सन 2008 में जीडीपी और कॉर्पोरेट आय के मामले में भारत और अमेरिका दोनों 7 फीसदी के समान स्तर पर थे। आज यह अनुपात अमेरिका में 10 फीसदी और भारत में केवल 2 फीसदी है। देश में कारोबारी मुनाफा पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। हमारी कॉर्पोरेट आय बीते आठ वर्षों में 5 फीसदी से भी कम रही है। आय में इस गिरावट की तमाम वजह हैं। वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए में सुधार, उच्च कर दर, तकनीकी विसंगति, आर्थिक झटके, निजी निवेश में कमी, रुपये का अधिमूल्यन आदि ऐसे ही कारक हैं। इन तमाम बातों के बावजूद सचाई यही है कि कोई भी कॉर्पोरेट मुनाफे में सुधार का अनुमान लगाने में सफल नहीं रहा। कोई नहीं कह सकता कि इसमें कब और कितना सुधार आ सकता है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि कॉर्पोरेट मुनाफा जीडीपी के हिस्से के रूप में हमेशा गिरता नहीं रह सकता।

हम पहले ही निम्नतम स्तर पर हैं। यहां से केवल सुधार संभव है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा कमजोरी को देखें तो एक और वर्ष हमें निराशा का सामना करना पड़ सकता है। बाजार के विस्तार का दौर समाप्त हो चुका है। ऐसे में बॉन्ड प्रतिफल में 100 आधार अंकों की गिरावट के बावजूद बाजार कमजोर पड़ रहा है। मजबूत आय वृद्धि के अभाव में बाजार में सुधार होता नहीं दिखता। अधिकांश निवेशक इंतजार करके थक चुके हैं और वे अब देश में आवंटन तभी बढ़ाएंगे जब आय में सुधार नजर आएगा। मौजूदा दर पर बाजार काफी महंगे हैं।

दूसरा, अर्थव्यवस्था वाकई कमजोर है। कॉर्पोरेट आय बीते कई वर्ष के निचले स्तर पर है। निवेशकों को कंपनियों से प्राय: बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। कारोबारी उत्साह नदारद है। हर कोई केवल नकदी जुटाने की बात कर रहा है।

नई क्षमता तैयार करने में किसी की रुचि नहीं नजर आ रही। मांग भी प्रभावित हुई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। कई कारोबारों को ऋण नहीं मिल रहा है। कारोबारी जगत का आत्मविश्वास हिला हुआ है। सरकार ने दरें कम करने तथा खपत और निवेश बढ़ाने का प्रयास किया है। इससे मदद मिलेगी लेकिन निवेशकों को भूमि, श्रम और न्यायिक सुधारों की भी जरूरत है। वे चाहते हैं कि देश कारोबारी दृष्टि से सुगम बने। सरकार के पास आर्थिक योजना है लेकिन उसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

तीसरा, यह भावना घर कर चुकी है कि भारत आर्थिक नीति में वाम रुझान अपना रहा है। यह सही है कि हमें औसत भारतीयों की जीवन गुणवत्ता सुधारने में अधिक से अधिक व्यय करने की आवश्यकता है। मौजूदा सरकार की जीत में ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं में सुधार की अहम भूमिका रही है। इसमें सड़क, आवास, बिजली और घरेलू गैस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। परंतु अभी काफी कुछ किया जाना है, जिसके लिए धन की आवश्यकता है।

मौजूदा रुख में तो संसाधन जुटाने के लिए सीमित कर आधार पर जी जोर दिया जा रहा है। इससे कारोबारियों में उत्साह नहीं पनप पा रहा। यही मूल आशंका है। इसमें दो राय नहीं कि देश के उद्योगपतियो ने भी तंत्र का खूब दुरुपयोग किया है। एनपीए संकट पर नजर डालिए। कई लोगों को दंडित किए जाने की आवश्यकता है।

परंतु हर बड़ा भारतीय उद्योगपति ठग या धोखेबाज नहीं है। यह भी सच है कि रोजगार तैयार करने काम निजी क्षेत्र ही करेगा। हमें कर दायरा बढ़ाने का तरीका तलाशना होगा। साथ ही सरकारी परिसंपत्ति की बिक्री तेज करनी होगी ताकि जरूरी राशि जुटाई जा सके। ग्रामीण भारत में संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए हम सरकारी उपक्रमों को लाखों करोड़ रुपये की राशि नहीं देते रह सकते। फिर चाहे वे बैंक हों, एयर इंडिया या बीएसएनएल अथवा एमटीएनएल जैसी कंपनियां।

इसके अतिरिक्त देश में निवेश के प्रतिफल में भी इजाफा हो रहा है। एनसीएलएटी ने हाल में एस्सार स्टील पर जो निर्णय दिया है वैसे मामलों से जोखिम का प्रीमियम बढ़ेगा। अगर जोखिम प्रीमियम बढ़ता है तो बाजार को सस्ता होना होगा ताकि उच्च कर पूर्व प्रतिफल दिया जा सके। सरकारी इक्विटी बाजार अभी सस्ते नहीं हैं।

फिलहाल देश में रुझान बहुत कमजोर हैं। यह बात घरेलू निवेशकों और उद्योगपतियों दोनों पर लागू होती है। यह नकारात्मकता वैश्विक निवेशकों को प्रभावित कर रही है। ऐसा लगता नहीं कि वैश्विक निवेशक, घरेलू निवेशकों से पहले निकासी करेंगे। हमें घरेलू रुझानों पर नजर रखनी होगी। उसके लिए हमें देश को कारोबारी दृष्टि से सुगम बनाने पर ध्यान देना होगा। फिर चाहे मामला करों का हो, नियमन का या सुधार का।

निजी क्षेत्र को आर्थिक वृद्धि में साझेदार बनाएं, दुश्मन नहीं

नीति नियम

मिहिर शर्मा

कैफे कॉफी डे का साम्राज्य खड़ा करने वाले संस्थापक वी जी सिद्धार्थ की दुखद मौत ने तीखी बहस छेड़ दी है कि क्या भारत और भारतीय राज्य का उद्यमियों, उद्योगपतियों और कारोबार जगत के प्रति दोस्ताना रवैया कम होता जा रहा है? अपने पीछे छोड़कर गए पत्र में सिद्धार्थ ने कहा है कि वह आयकर अधिकारियों के उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। हालांकि आयकर विभाग ने इस आरोप को पूरी तरह नकार दिया है लेकिन लोग इस दावे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों की नजर में आयकर विभाग ने माइंडट्री कंपनी में सिद्धार्थ के शेयरों को बेचने से रोककर उनका उत्पीड़न ही किया क्योंकि अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी था।

लेकिन आज जताई जा रही चिंता इस मामले के गुण-दोषों से आगे तक जाती है। काले धन के खिलाफ सरकार के जुबानी अभियान के दौर में पैदा हुई आम शंका से इसे बल मिलता है जो आगे चलकर एक डरावने कानून में तब्दील हो गया। पिछले आम बजट में वित्त मंत्री ने अति-संपन्न लोगों पर अधिक कर लगाने की घोषणा की है। हालांकि अधिकतर लोगों के लिए यह कोई खास समस्या नहीं है। लेकिन कर में बढ़ोतरी से निकला संदेश परेशान करता है। यह इंदिरा गांधी के दौर में केंद्र के नकली समाजवादियों द्वारा पैदा किए गए शोर की वापसी जैसा है। बजट में किए गए अन्य प्रावधानों के साथ इसे जोड़कर देखने की जरूरत है। मसलन, अब अगर कंपनियां अपने मुनाफे का दो फीसदी हिस्सा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च करने में नाकाम रहती हैं तो उन पर आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। लाभ के एक हिस्से का भुगतान अनिवार्य किया जाना किसी कर से कम किस तरह है? और सरकार गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के फायदे के लिए कंपनियों पर कर भला क्यों लगा रही है? यह तो सत्तारूढ़ दल के वैचारिक सहयोगियों को अधिक नकदी मुहैया कराने का एक तरीका भर है जिसका इस्तेमाल राज्य के समानांतर एक हिंदुत्ववादी प्रतिष्ठान खड़ा करने में किया जाना है।

बजट में कुछ कर अधिकारियों को अधिक ताकत दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। मसलन, सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों को अब यह ताकत दे दी गई है कि 'राजस्व के लिहाज से खतरा' नजर आने वाले लोगों को वे हिरासत में ले सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कुछ चीजें निश्चित रूप से बेहतर हुई हैं। उदाहरण के लिए, कर प्रक्रिया में शुरुआती मानव संपर्क कम करने की लगातार कोशिश हुई है। यह भी सच है कि लोगों के बीच धारणा बन गई है कि सरकार कारोबार जगत से एक-एक पैसा निचोड़ लेना चाहती है। ऐसी धारणा बनाने में सरकार के उच्च अधिकारियों और सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेताओं का मिला-जुला हाथ रहा है।

सीधी सी बात है कि भारत इस समय इस तरह का माहौल बनने का बोझ नहीं उठा सकता है। हम वर्षों से जारी निवेश संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इसकी हालत में सुधार आना अभी बाकी है। निजी निवेश नहीं बढ़ने तक भारत उच्च वृद्धि के रास्ते पर नहीं लौट पाएगा जबकि रोजगार पैदा करने और समृद्धि लाने के लिए यह जरूरी है। लेकिन निवेशकों को डराने से निजी निवेश नहीं लौटेगा। क्या हम चीन जैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां सरकार को बड़े पैमाने पर पूंजी पलायन की आशंका सताती रहती है? पहले ही सरकार काले धन संबंधी कानून के आपराधिक प्रावधानों का दायरा अनिवासी भारतीयों तक बढ़ा चुकी है। सरकार को यही लगता है कि बहुत सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और अभियोजन से बचने के लिए ही वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यह मौजूदा हालात की गलत वजह तलाशने का मामला है। अगर लोग खुद देश छोड़कर नहीं भी जा रहे हैं तो वे अपने हितों और आय के स्रोतों को भौगोलिक रूप से विस्तारित करना चाह रहे हैं। कुछ साल पहले एक चर्चित कारोबारी घराने के वारिस से जब मैंने उनकी भावी कारोबारी रणनीति के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वह अब अपने समूह की आय का बड़ा हिस्सा विदेशी कारोबार से लाना चाहते हैं। उस उद्योगपति का कहना था कि वह राजनीतिक जोखिम को नगण्य करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। अगर भारत के उद्यमी खुद ही उत्पीड़न के डर से भारत में निवेश करने से संकोच कर रहे हैं तो फिर कोई विदेशी निवेशक ऐसा क्यों करेगा?

सरकार के पास पैसे की बहुत किल्लत है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को ठीक से लागू कर पाने में नाकामी के चलते सरकार के पास पैसे नहीं हैं। इसके चलते सरकार न केवल राजकोषीय स्थिति की सही तस्वीर छिपा रही है बल्कि अधिक पैसे जुटाने के लिए वह आसपास के कमजोर ठिकानों की भी तलाश में है। भारत में कारोबार करना हमेशा ही एक कमजोर निशाना रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन और नोटबंदी के बाद से ही यह धारणा मजबूत होती गई है कि लंबे समय तक अमीरों को संरक्षण दिया जाता रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें ठोक-बजाकर सही कर देगी।

इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सकता है कि भारत में असमानता एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन राज्य का मनमानापन और संपत्ति एवं व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में समझ का अभाव होना भी इसकी एक समस्या रही है। हम असमानता एवं वृद्धि संबंधी समस्याओं का समाधान केवल तभी कर सकते हैं जब हम निजी क्षेत्र के भीतर निवेश में तेजी लाने वाला सुरक्षा अहसास पैदा कर पाएंगे। ऐसा न होने तक भारत मोदी सरकार के दौरान फिसलन की राह पर ही रहेगा और 1970 के दशक के अंधेरे दिनों की तरफ लौटना जारी रखेगा।

'राजस्व के हित' के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है लेकिन राजस्व का वास्तविक हित अर्थव्यवस्था की प्रगति में है। और ऐसा होने के लिए निजी क्षेत्र को राजस्व का साझेदार होना चाहिए, न कि कोई दुश्मन।

कानाफूसी

चेतावनी लड्डू के साथ

केरल के पालक्कड में पिछले दिनों मोटर साइकिल सवार उस समय चकित रह गए जब यातायात पुलिस ने उनके बीच 300 से अधिक लड्डू बांटे। ये लड्डू किसी त्योहार के उपलक्ष्य में नहीं दिए गए। दरअसल इस मिष्ठान्न वितरण के साथ पुलिस ने उन्हें एक चेतावनी भी दी। कहा गया कि आज तो लड्डू बांटे जा रहे हैं लेकिन अगर आपने यातायात के नियमों का पालन नहीं किया तो अगली बार इसके स्थान पर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। यह चेतावनी उन दोपहिया वाहन चालकों को दी गई जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे। दरअसल पुलिस का यह आयोजन जागरूकता अभियान का हिस्सा था ताकि लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए समझाया जा सके। केरल में अब दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही कार में पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना भी अब आवश्यक है।

किशोर की दूरी

जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी आरंभ कर दी है। परंतु पार्टी के पेशेवर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहीं और व्यस्त हैं। किशोर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक पेशेवर अनुबंध के तहत काम कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जदयू की गतिविधियां अब दिल्ली स्थानांतरित हो गई हैं जहां राज्य सभा सदस्य राम चंद्र प्रसाद सिंह ने दो अहम पहलुओं पर काम करना आरंभ कर दिया है। पहला, संभावित प्रत्याशियों की पहचान करना और दूसरा गठबंधन साझेदार भाजपा के साथ संतुलन कायम करना। जदयू सूत्रों के मुताबिक पार्टी में नंबर दो की किशोर की कुर्सी काफी हद तक प्रतीकात्मक है और पार्टी में अध्यक्ष नीतीश कुमार के बाद सिंह की ही चलती है। चूंकि कुमार की गठबंधन प्राथमिकताएं तथा पार्टी करीबियों की सूची तेजी से बदलती रहती हैं इसलिए कोई सुनिश्चित होकर कुछ नहीं कह सकता।

आपका पक्ष

देश की अर्थव्यवस्था के लिए बुरा दौर

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। लेकिन हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था पांचवें स्थान से फिसलकर सातवें स्थान पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था की जीडीपी का आकार 2,762.32 अरब डॉलर का है। भारत को अगर 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना है तो 2025 तक लगातार 8 फीसदी से वृद्धि जरूरी है। लेकिन जनवरी-मार्च की तिमाही के आंकड़े खासे निराशाजनक हैं क्योंकि इस तिमाही में जीडीपी वृद्धि 5.8 फीसदी रही। यह पांच साल का निचला स्तर है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। सरकार आर्थिक मोर्चे पर अब तक असफल रही है क्योंकि कई क्षेत्रों की कंपनी में छंटनी शुरू हो गई है। खबरों के अनुसार वाहन कलपुर्जा उद्योग में 10 लाख नौकरी जाने का अंदेशा है। ऐसे कई उदाहरण अर्थव्यवस्था की बुरी हालत दर्शा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 72.7 करोड़ डॉलर घट गया है। आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार अभी 429.65 अरब डॉलर रह गया है। अगर देश को 2025 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार करने के साथ तकनीक एवं कौशल शिक्षा को महत्त्व देना होगा क्योंकि भारतीय श्रमिकों की उत्पादकता अन्य देशों के मुकाबले कम है। उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए कृषि सुधार के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। उद्योगों पर आज भी अधिक कर लगाया जाता है। इससे कई उद्योग हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए कर प्रणाली में सुधार की जरूरत है। बेरोजगारी एवं श्रमिकों की कम आय के चलते घरेलू बचत दर निम्न स्तर पर है जिससे देश को विदेशी निवेश पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए बेरोजगारी हटाकर श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को उपाय खोजना होगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिश होनी चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 हजार अरब डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है

गोवा में महिलाओं को बराबरी का हक

महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने संबंधी एक विधेयक पिछले दिनों गोवा विधानसभा में पारित किया गया। यह महिलाओं को बराबरी का हक देने में एक बड़ा कदम है। इसके तहत महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति मिल जाएगी। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। लेकिन महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने को बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि कई बार महिलाओं को इसलिए पदोन्नति नहीं दी जाती क्योंकि वे रात्रि पाली में कार्य नहीं करती हैं। अब महिलाओं को पदोन्नति नहीं देने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इस कानून से महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ेगा तथा वे स्वावलंबी बनेंगी। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है। रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए।

अदिति कुमारी, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।